MR. CHAIRMAN: The latest report says that coffee also is not that much useful.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: My suggestion to the Government is to reduce the applied rates for green coffee imports under the Indo-ASEAN Free Trade Agreement without affecting the domestic export.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, it is a very good suggestion. In fact, this Free Trade Agreement with ASEAN was executed about ten years ago. Our own studies show that we have not been able to get as much benefit out of the FTA. We have opened up our markets for many other countries to the detriment of India's interest and Indian coffee growers' interest. We have already initiated dialogue with ASEAN countries. I am happy to share with the House, through you, Mr. Chairman, Sir, that ASEAN has agreed to a review of the FTA. We will take up various issues in the review and then we will report it in the House.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Sir, I would like to know from hon. Minister whether the Government has formulated any coffee export policy providing external support for export of value-added coffee as an Indian brand for external promotion.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, this is a very good point because Indian coffee is truly remarkable in terms of its taste and quality. The Coffee Board has recently worked very actively to create an India brand of coffee rather than focusing on different companies having their own brands. They are working towards creating a brand equity of Indian coffee and then within that there would be subset of the various brands that are already available. It is work in progress. They are working with several companies, both in India and internationally, to see how that brand can be expanded.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 125. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

*125. *[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित थे।]*

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को बीमा दावों का भुगतान किया जाना

*125. **श्री राम विचार नेताम**: क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीमा कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावों के अनुरूप भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए इस प्रकार के दावों के निपटान के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत सभी प्रस्तुत दावों का रबी 2018-19 तक संबंधित बीमा कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया गया है जिसमें नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांस्फर (एनईएफटी) से संबंधित मामलों के कारण एचडीएफसी-जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीफ 2018 के मौसम के लिए लगभग 20 लाख रूपए का लम्बित भुगतान शामिल नहीं है। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी न किए जाने के कारण पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्यूबीसीआईएस) के तहत रबी 2018-19 के लिए 6.23 करोड़ रूपए के दावों का भुगतान भी लंबित है। पीएमएफबीवाई के प्रारंभ से कुल प्रस्तुत दावों, स्वीकृत दावों तथा बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है-

(₹ करोड़ में)

मौसम	प्रस्तुत दावों की राशि	स्वीकृत दावों की राशि	भुगतान किए गए दावों की राशि
खरीफ 2016	133.04	133.04	133.04
रबी 2016-17	27.03	27.03	27.03
खरीफ 2017	1308.92	1308.92	1308.92
रबी 2017-18	79.09	79.09	79.09
खरीफ 2018	1003.86	1003.86	1003.66
रबी 2018-19	60.78	54.55	54.55

(ग) और (घ) यह विभाग पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी कर रहा है जिसमें बीमा कंपनी द्वारा दावों का समय पर निपटारा करना भी शामिल है। बीमा

कंपनी द्वारा दावों का देरी से निपटारा करने तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों को विलंब से जारी करने के लिए पैनल इंटरेस्ट के प्रावधान को इस स्कीम के संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में शामिल किया गया हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अर्थदंड की, यदि कोई हो, गणना करें तथा संबंधित बीमा कंपनियों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे दावों की राशि के साथ दंडात्ममक धनराशि का भुगतान किसानों को करें।

*125. *[The Questioner was absent.]*

Payment of insurance claims to farmers of Chhattisgarh under PMFBY

†*125. SHRI RAM VICHAR NETAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the insurance companies have not made payments to the farmers in the State of Chhattisgarh against the claims made under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY);

(b) if so, the details thereof and the steps taken so far by Government in this regard;

(c) whether Government has chalked out any action plan for disposal of such claims under PMFBY; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No Sir. All the admissible claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) have been paid by the concerned insurance company till Rabi 2018-19 season except approximately ₹ 20 lakh for Kharif 2018 season by HDFC-General Insurance Company Ltd. due to National Electronic Funds Transfer (NEFT) related issues. However, claims of ₹ 6.23 crore for Rabi 2018-19 are also pending under Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBC1S) due to non-release of premium subsidy from the State Government of Chhattisgarh. Details of total admissible claims, claims approved and claims paid by insurance companies since inception of the PMFBY/RWBCIS are given in the following table:

†Original notice of the question was received in Hindi.

(₹ in crore)

Season	Admissible Claim Amount	Approved Claim Amount	Claims Amount paid
Kharif 2016	133.04	133.04	133.04
Rabi 2016-17	27.03	27.03	27.03
Kharif 2017	1308.92	1308.92	1308.92
Rabi 2017-18	79.09	79.09	79.09
Kharif 2018	1003.86	1003.86	1003.66
Rabi 2018-19	60.78	54.55	54.55

(c) and (d) This Department is regularly monitoring the implementation of PMFBY including timely settlement of claims by insurance companies. Provisions of payment of penal interest for late settlement of claims by insurance companies and late release of funds by State Governments have also been included in the Revised Operational Guidelines of the scheme. Accordingly, all State Governments including Chhattisgarh have been advised to calculate penalty, if any, and direct the concerned insurance companies for payment of penal interest to the farmers alongwith the claim amount.

डा. अमर पटनायक: सर, इसके बारे में मॉर्निंग में भी बात हुई थी।

MR. CHAIRMAN: Yes, you have specifically raised that issue.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, my question to the hon. Minister is कि ओडिशा में ACF and YCF यूज़ करके जो claims settle नहीं हुए हैं, क्या उनका समाधान करके फार्मर्स को, उनका जो legitimate dues हैं, वे मुहैया कराएंगे? Would the Minister, at least, review this situation in Odisha because there have been several strikes and farmers are on the roads for the last four-five months?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति महोदय, यह सवाल छत्तीसगढ़ के संबंध में है, मगर जब आपने सुबह स्पेशल मेंशन में इसका जिक्र किया था, मैंने उसी का नोट बना कर अपनी जेब में रख लिया है। उसमें आपका grievance है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ स्टेट के figures नहीं मिल रहे हैं और उसकी गलती यह है कि वह सिस्टम को follow नहीं कर रही है, मैं इसका संज्ञान लूँगा और इस पर जो कार्रवाई की जाएगी, मैं उसकी जानकारी भी आपको दूँगा।

श्री सभापति: श्रीमती छाया वर्मा। चूँकि यह छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक है, इसलिए मैं आज आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, otherwise नहीं।

श्रीमती छाया वर्मा: धन्यवाद, सर। सर, 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत तहसील को एक यूनिट मान कर किसानों को यह दिया जाता है। इसके कारण किसान भटकते रहते हैं और वे समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें बीमा की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ग्राम पंचायत को 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' का यूनिट बनाएंगे?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बता दूँ कि 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' में राज्य को अपने पाकों को अधिसूचित करना होता है कि कौन पाक मुख्य है और कौन पाक गौण है। यदि राज्य का कोई मुख्य पाक है, तो उसके लिए यूनिट गाँव ही है, यह अभी से ही मंजूर है। यदि क्रॉप गौण के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो उसके लिए यूनिट ताल्लुका या मंडल होता है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 126. Shri K.J. Alphons.

Impact of global warming on agricultre production

*126. SHRI K.J. ALPHONS: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether due to global warming, there is unpredictability regarding monsoon and as a result, agriculture is going to be badly affected; and

(b) if so, the steps taken by Government to increase agricultural production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There is no unpredictability regarding monsoon. It is a fact that, Global Warming associated with the increase in concentration of green house gases in the atmosphere is one of the reasons for the increase in extreme weather events including extremely heavy rainfall during monsoon season.

Due to global warming agriculture sector is likely to be affected and climate change is expected to impact yields of agriculture crops in a business as usual scenario. The simulation studies using integrated modelling framework showed that rainfed rice yields in India are projected to reduce marginally (<2.5%) in 2050 and 2080 scenarios